प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

09.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा– विधायी निकायों में महिलाओं को आरक्षण से और अधिक जीवंत व सहभागी बनेगा लोकतंत्र।
- राज्य के एक सौ 51 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू करने से छात्र नामांकन में हुई वृद्धि–मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन स्कूलों में तीन संकाय शुरू करने के दिए निर्देश।
- राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पैकेज भुगतान में किया बदलाव।
- प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव को हाईजैक करने का लगाया आरोप।
- अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्री रेणुका जी बांध परियोजना के पहले चरण का कार्य शुरू–लोगों को 4 दशक पुरानी मांग पूरी होने की जगी आस।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत व सहभागी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। एक वीडियो में समाचार पत्रों में दिए गए अपने विशेष लेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण से जुडे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया गया है।

मुख्यमंत्री

राज्य के एक सौ 51 सरकारी स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पैटर्न लागू करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और स्कूलों में छात्र प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन सभी स्कूलों में 3 शैक्षणिक संकायों मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कई कदम उठाए हैं और अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल देश में 21वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

हिमकेयर

इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमकेयर योजना को पारदर्शी व सशक्त बनाने के लिए योजना के तहत पैकेज भुगतान में बदलाव किया गया है। आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की। हिमकेयर योजना के तहत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों द्वारा उपभोग्य सामग्री व वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों द्वारा क्लेम के साथ वास्तविक व्यय के बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

जबकि बिल में पंजीकरण शुल्क, बैडचार्ज, नर्सिंग व बोर्डिंग शुल्क खर्च दावों का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह सर्जन एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक और परामर्शदाता की फीस, ऑपरेशन थियेटर शुल्क, शल्य उपकरणों की लागत, दवाईयां व औषधियां और मरीज के लिए भोजन के प्रतिपूर्ति दावे भी बिलों का हिस्सा नहीं होंगे। योजना में इस युक्तिकरण के बाद जो राशि बजट में सरकारी अस्पतालों को प्रदान की जाएगी वो हिमकेयर पैकेज का हिस्सा नहीं होगी और सरकार द्वारा इन मदों में आबंटित धनराशि का प्रावधान सरकारी अस्पतालों के बजट में ही कर दिया जाएगा।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज ग्रेटर नोयडा में आयोजित 51वें राष्ट्रीय नैदानिक मनोविज्ञान सम्मेलन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ए.आई. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, प्रभावी और व्यक्तिगत बनाने की क्षमता रखती हैं जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार मिल सकता है। राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और टेलीमानस जैसे कार्यक्रम के माध्यम से दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। कविन्द्र गुप्ता ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत करने पर बल दिया और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत बताई।

अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने और जलशुद्धिकरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए करीब 2 हजार करोड़ रूपए की व्यापक योजना लागू की जाएगी। ऊना जिले के हरोली में जलशक्ति विभाग के नवनिर्मित विश्राम गृह के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आधुनिक तकनीक आधारित जलशुद्धिकरण प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। अग्निहोत्री ने बताया कि ऊना जिला में पेयजल व सिंचाई से संबंधित करीब एक हजार करोड़ रूपए की परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों को सुनियोजित तरीके से हाईजैक करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष तक चुनाव टालने के लिए जोर लगाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। लेकिन जब अदालत ने 31 मई से पहले चुनाव करवाने के स्पष्ट आदेश दिए तो अब सरकार ने नया खेल शुरू कर दिया है। बिंदल ने आरोप लगाया कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरक्षण रोस्टर को रोजाना बदला जा रहा है।

चन्द्र कुमार

कृषि व पशुपालन मंत्री चन्द्र कुमार ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्राकृतिक खेती व पशुपालन की अहम भूमिका है। वे आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। चन्द्र कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का निवारण उनके घर–द्वार पर सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्की, हल्दी और अदरक के मूल्य में वृद्धि की है। कृषि मंत्री ने पशुपालकों से दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर उनका पंजीकरण कराने का आहवान किया।

रेणुका परियोजना

सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र में गिरी नदी पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्री रेणुका जी बांध परियोजना के पहले चरण का कार्य आज शुरू हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व स्थानीय विधायक विनय कुमार

ने निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की करीब 4 दशक पुरानी मांग अब पूरी हो रही है और बांध के बनने से उनकी आर्थिकी में सुधार होगा।

विक्रमादित्य

लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। आज सुंदरनगर के समीप खिलड़ा स्थित एक निजी संस्थान के वार्षिक समारोह में उन्होंने युवाओं से इंजीनियरिंग व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रदेश के विकास में योगदान देने का आहवान किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहा है और बेमौसमी वर्षा का असर कृषि व बागवानी पर पड़ रहा है जो चिंता का विषय है।

आवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 8 सौ 8 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए 8 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन स्कूलों में संगीत, ड्राइंग, संस्कृत, फिजिकल एजूकेशन, हिंदी, इतिहास और भूगोल अध्यापकों के पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर लिंक 17 अप्रैल सुबह 10 बजे से लेकर 8 मई तक खुला रहेगा।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा– विधायी निकायों में महिलाओं को आरक्षण से और अधिक जीवंत व सहभागी बनेगा लोकतंत्र।
- राज्य के एक सौ 51 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू करने से छात्र नामांकन में हुई वृद्धि–मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन स्कूलों में तीन संकाय शुरू करने के दिए निर्देश।
- राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पैकेज भुगतान में किया बदलाव।
- प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव को हाईजैक करने का लगाया आरोप।
- अंतर्राष्ट्रीय महत्व की श्री रेणुका जी बांध परियोजना के पहले चरण का कार्य शुरू–लोगों को 4 दशक पुरानी मांग पूरी होने की जगी आस।